

91

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक / 2016 पुनर्विलोकन ।

23/2016-I-16

अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल रजाक आयु 51 साल जाति मुसलमान धन्धा खेती निवासी वार्ड क्रमांक 6 पठान रोड, रतोदन दरवाजा बडौदा तेहसील बडौदा, जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

— आवेदक ।

श्री मुकेश माणिक अमिताभ
द्वारा आज दि 04-7-16 को प्रस्तुत

बिर्द्ध और कोर्ट 4.7.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुद्ध

- (1) कैलाशी वाई पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण जाति माली उम्र 59 साल निवासी वार्ड नम्बर 4 खटीक मोहल्ला कस्बा बडौदा तेहसील बडौदा जिला श्यौपुर म0प्र0 ।
- (2) लीलाधर पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण जाति माली उम्र 59 साल निवासी वार्ड नम्बर 4 खटीक मोहल्ला कस्बा बडौदा तेहसील बडौदा जिला श्यौपुर म0प्र0 ।
- (3) धनराज पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण जाति माली उम्र 59 साल निवासी वार्ड नम्बर 4 खटीक मोहल्ला कस्बा बडौदा तेहसील बडौदा जिला श्यौपुर म0प्र0 ।
- (4) पटवारी हल्का कस्बा बडौदा द्वारा तेहसीलदार बडौदा जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

— अनावेदकगण।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 489-एक/2016 कैलाशी वाई एवम् अन्य बिरुद्ध अब्दुल रफीक में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 के लिये पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता ।

मान्यवर महोदय ,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1- यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण (कैलाशी वाई, लीलाधर, धनराज,) ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी श्यौपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/2013-2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 के बिरुद्ध निगरानी पेश की गई है। जब कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी श्यौपुर द्वारा उपरोक्त अपील प्रकरण क्रमांक 74/2013-2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय तेहसीलदार बडौदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2013-2014 अ (6) अ में पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 निरस्त किया जा कर आवेदक / अब्दुल रफीक की अपील स्वीकार फरमायी गई थी।

2- यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 प्रथम अपील में पारित किया गया था। प्रथम अपील में पारित आदेश के बिरुद्ध सक्षम न्यायालय में द्वितीय अपील पेश करने का बिधि में प्रावधान है न कि निगरानी करने का पुनर्विलोकन अधिन आदेश माननीय न्यायालय को प्रमित करके बिधि के प्रावधानो के बिपरीत पारित पारित हुआ है इसलिये पुनर्विलोकन अधिन आदेश को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

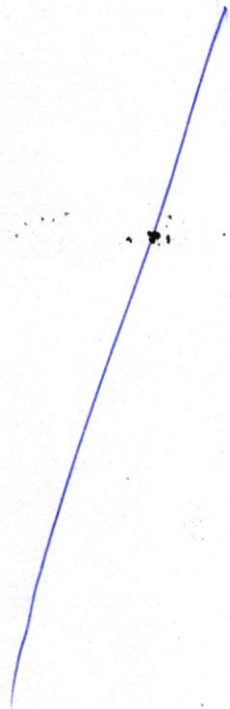
पुर्विलोकन के आधार

1- यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 प्रथम क्रमशः—2

MRG

hse

22/10/2020 (Date)



5-10-16

आवेदक अवि. की मुद्रा
मागीप उपर। आवेदक अवि.
का सिपे इन किया गया। आवेदक
अवि. का सिपे इन लीकाए जाने
हुए प्रकार मो 2 जेस में समावे
किया गया है जो दाएँ सिपे

[Handwritten signature]
20/10/20

[Handwritten mark]